The Asian Age (Mumbai) 22 July, 2018

'CHAKKA JAM TO INTENSIFY FROM MONDAY'

AGE CORRESPONDENT
MUMBAI, JULY 21

As the All India Motor Transport Congress' (AIMTC) indefinite nationwide 'chakka jam' over the diesel price hike entered its second day, the AIMTC said that it will intensify its strike from Monday, as 2,500 trucks that supply essential commodities to Mumbai will participate in the agitation for a day. Meanwhile, talks between AIMTC and the union government failed to resolve the issue. The members of the AIMTC also protested at Azad Maidan on Saturday.

Vice-President of Bombay Goods Transport Association, Ashok Rajguru said, "2,500 trucks supplying essential commodities such as milk, vegetables, food grain, fruits and eggs in Mumbai would be joining the agitation on Monday, as the government has turned a deaf ear over our demands."

Bal Malkit Singh, Chairman, Core Committee of AIMTC said, "Day two consolidated the agitation. There have been very positive reports from across the country and all state, district and taluka level associations and unions and their members' have extended unstinting support to this movement."

Mr. Singh claimed that the industry has already started to feel the pinch. ASSOCHAM quoted loss of about ₹20,000 crore due to the strike and urged the government's intervention to speedily resolve issues as transporters have been reel-

Dainik Bhaskar

22 July, 2018

अब ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ेगा डिस्काउंट इस साल सवा करोड़ खरीदार नए जुड़ेंगे

पीडब्ल्यूसी और क्रिसिल के अनुसार बड़ी कंपनियों के आने से मिलेगी ज्यादा छूट

• 2020 तक ऑनलाइन खरीदी में हो जाएंगे ढाई से तीन गुना महिला-बुजुर्ग

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया | नई दिल्ली

भारत में ऑनलाइन रिटेल बाजार में एक बार फिर से डिस्काउंट और विलय-अधिग्रहण का दौर देखने को मिल सकता है। बाजार विश्लेषकों और रिटेल कंपनियों के मुताबिक वालमार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण और मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह द्वारा ई-कॉमर्स बिजनेस में उतरने की घोषणा के बाद तेज बदलाव देखने को मिलेंगे। लोगों के पास सामान खरीदने के अधिक विकल्प होंगे और उन्हें अधिक डिस्काउंट भी मिल सकता है। होम डिलीवरी पहले से तेज होने की उम्मीद है। एसोचैम-रिसर्जेंट की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वर्ष के अंत तक ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या 12 करोड़ होने का अनुमान है। बीते वर्ष तक यह संख्या 10.8 करोड़ थी। इस कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक देश में सर्विसेज छोड़कर ई-कॉमर्स का वर्तमान बाजार करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 तक ई-कॉमर्स बिजनेस 2.5 लाख करोड़ से 2.7 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। 2020-21 तक ई-कॉमर्स के 33 से 38 फीसदी वार्षिक की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है।

पीडब्ल्यूसी के पार्टनर एंड लीडर डील स्ट्रैटजी संकल्प भट्टाचार्य ने कहा कि अभी ई-कॉमर्स में विशेष अवसरों को छोड़कर डिस्काउंट आदि कम हो गया था। रिलायंस द्वारा रिटेल ई-कॉमर्स बिजनेस में आने की घोषणा के बाद एक बार फिर से डिस्काउंट और लंबी-लंबी सेल का दौर आएगा। जैसे किसी खास प्रोडक्ट पर पहले 10 से 15 प्रतिशत डिस्काउंट मिलता था तो अब उस पर 15 से 20 प्रतिशत डिस्काउंट मिल सकेगा। देश में डेढ़ से दो हजार ई-कॉमर्स और उससे जुड़ी व्यापार वाली कंपनियां हैं। विलय-अधिग्रहण का दौर फिर से देखने को मिलेगा। भविष्य में इस क्षेत्र में तीन से चार बड़ी कंपनियों का ही वर्चस्व रहेगा।

वहीं क्रिसिल रिसर्च के निदेशक राहुल प्रीथियानी ने कहा कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 के पांच वर्ष के दौरान ई-कॉमर्स इंडस्ट्री 45 से 50% की रफ्तार से बढ़ी है। आने वाले वर्षों में यह 33 से 38 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ेगी और 2020-21 तक इसके 2.5 से 2.7 लाख करोड़ रु. होने की संभावना है। आने वाले वर्षों में दो से तीन कंपनियों की हिस्सेदारी ऑनलाइन रिटेल बाजार में 75% की होगी। वालमार्ट के अधिग्रहण के बाद उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बड़ी रेंज और बेहतर सर्विस देखने को मिलेगी। शेष | पेज 08 पर

इस वर्ष 65% यूजर मोबाइल से करेंगे शॉपिंग

एसोचैम-रिसर्जेंट की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 तक 40 से 45 फीसदी उपभोक्ता मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में कर रहे थे, जबकि वर्ष 2018 में 60 से 65 फीसदी उपभोक्ता ऐसा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ों और एसेसरीज में 54 फीसदी लोग, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में 43 फीसदी लोग और इलेक्ट्रॉनिक्स में 33 फीसदी लोग बार-बार इन्हीं प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं। ऑनलाइन खरीदी करने वाले उपभोक्ताओं में खरीदी के बाद नगद (कैश ऑन डिलेवरी) भुगतान 58 फीसदी लोग पसंद करते हैं, जबकि डेबिट कार्ड के द्वारा 23 फीसदी और क्रेडिट कार्ड के द्वारा 17 फीसदी लोग खरीदी करते हैं।

ऑनलाइन मार्केट में कंपनियों की हिस्सेदारी

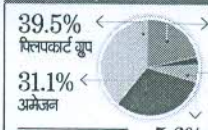

स्रोत : फॉरेस्टर रिपोर्ट 2017

टेक्नोपैक कंसल्टिंग के चेयरमैन अरविंद सिंघल के मुताबिक 5 वर्ष में ई-कॉमर्स से 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिला, अगले 5 वर्ष में 10 से 15 लाख लोगों को और रोजगार मिल पाएंगे।

अब ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ेगा डिस्काउंट...

प्रीथियानी ने बताया कि वर्तमान में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पूरी बिक्री में 70 से 75 फीसदी हिस्सेदारी रखता है और ग्रोसरी (किराना) की हिस्सेदारी दो से चार फीसदी है। आने वाले तीन वर्ष में ग्रोसरी की बढ़ोत्तरी सर्वाधिक होगी फिर भी बिक्री में हिस्सेदारी 10 फीसदी से कम रहेगी। बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बड़ी कंपनियां हलचल मचाएंगी और डिस्काउंट एक बार फिर से आ सकता है।

इस संबंध में बात करने पर टेक्नोपैक कंसल्टिंग के चेयरमैन अरविंद सिंघल ने कहा कि ई-कॉमर्स मार्केट दो हिस्सों में है। एक- सर्विसेज का मार्केट। इसमें इंश्योरेंस सर्विसेज, इंटरटेनमेंट, म्यूजिक-मूवी, एज्युकेशनल सर्विसेज हैं। दूसरा- ई-कॉमर्स (मर्चेंटाइल)। इसके सहारे वस्तुएं बेची जाती हैं। सिर्फ इसी मार्केट की बात करें तो हमारी कंपनी के हिसाब से करीब 16 से 18 अरब डॉलर के बीच हैं। इस तरह करीब 1.2 लाख करोड़ का बाजार है और पूरा रिटेल मार्केट करीब 700 बिलियन डॉलर का है। इस तरह दो सवा दो प्रतिशत का मार्केट है पूरे रिटेल बाजार का। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण पांच-सात साल में तो नहीं लेकिन 10 से 15 साल बाद ई-कॉमर्स में फूड और ग्रोसरी का मार्केट बड़ा हो जाएगा। अभी यह आधा बिलियन डॉलर का भी मार्केट नहीं है यह पांच साल में बढ़कर दो बिलियन डॉलर हो सकता है। ई-कॉमर्स में रिलायंस और वालमार्ट (फ्लिपकार्ट) जैसी कंपनियों की एंट्री के बाद इस सेग्मेंट में डिस्काउंट बढ़ेगा क्योंकि उनके पास इंवेंट्री के कारण ग्राहकों को मार्जिन देने की संभावना बनी रहती है। अमेरिका में हर एक वीकएंड पर सेल लगती है तो मुझे लगता है कि भारत में भी ई-कॉमर्स में वीकली सेल देखने को मिल सकती है। जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। ऑर्डर करने के बाद ग्राहकों को अब डिलीवरी और जल्दी मिलेगी। पिछले पांच वर्ष में ई-कॉमर्स से पांच से छह लाख लोगों को रोजगार मिला है, मुझे लगता है कि आने वाले पांच वर्ष में 10 से 15 लाख लोगों को और रोजगार मर्चेंटाइल ई-कॉमर्स से मिल पाएंगे।

एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत ने कहा कि ई-कॉमर्स बिजनेस का आकार देश में छोटा है, इसलिए इसकी ग्रोथ की संभावना बहुत है। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिलीवरी चैनल जैसे कोल्ड चैन आदि के बढ़ने से ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से बढ़ेगी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस क्षेत्र में कई अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। वालमार्ट और रिलायंस के आने के बाद नॉन फूड और किराना सामान भी तेजी से बिकेगा। एमएसएमई के लिए निर्यात के अवसर बढ़ेंगे। लोकल सोर्सिंग से किसानों को फायदा होगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा।

वालमार्ट इंडिया के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफीसर रजनीश कुमार ने कहा कि जरूरी मंजूरी के बाद हमारा विश्वास है कि वालमार्ट और फ्लिपकार्ट के द्वारा हम देश में सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हजारों किसानों, एसएमई सप्लायर्स और छोटे-छोटे निर्माताओं को भी तकनीकी और आर्थिक मदद कर पाएंगे। हम अपना थोक का कैश एंड कैरी व्यापार भी बढ़ाएंगे, हमारी योजना अगले चार से पांच वर्ष में 50 नए स्टोर खोलने की है। वालमार्ट इंडिया के इस वक्त 10 लाख सक्रिय ग्राहक हैं, जिनमें से 70 फीसदी छोटे किराना स्टोर हैं। वालमार्ट की योजना फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करने वाले उपभोक्ताओं को छोटे किराना स्टोर्स के द्वारा जल्द सामान घरों तक पहुंचाने की है।

मुकेश अंबानी की आरआईएल की योजना ऑनलाइन और रिटेल, दोनों को मिलाकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की है। वह सीधे तौर पर अमेजन और वालमार्ट इंक की फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को बनाने में ग्रुप की रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इंफोकॉम शामिल होंगी। आरआईएल की योजना हाइब्रिड ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन रिटेल को शुरू करने की है। यह प्लेटफॉर्म ग्रुप की टेलिकॉम सर्विस और 7,500 रिटेल स्टोर्स को साथ मिलाकर बनाया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और गूगल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश में उपभोक्ताओं का डिजिटल खर्च वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ा 45 अरब डॉलर का हिस्सा ई-कॉमर्स का होगा। इस अध्ययन के मुताबिक 2020 तक महिला खरीदारों की संख्या ढाई गुना और वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तीन गुना तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट का प्रयोग करने वाले 75 से 80 फीसदी लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं।